International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
ISSN -2393-8048, July-December 2020, Submitted in December 2020, iajesm2014@gmail.com

बंगलादेश के उद्भव में भारत की भूमिका

अनुपम कुमारी, अनुसन्धान विद्वान्, राजनीति विज्ञान विभाग, औ पी जे एस यूनिवर्सिटी, चूरू (राजस्थान)
डॉ दीपक, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, औ पी जे एस यूनिवर्सिटी, चूरू (राजस्थान)

परिचय

अन्य देशों के आंतरिक मामलों में और विशेष रूप से अपने पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना भारतीय विदेश नीति का एक सुसंगत और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। लेकिन दिसंबर 1970 में हुए पहले आम चुनाव के बाद पाकिस्तान में पैदा हुए सत्ता के लिए गंदे संघर्ष ने पूर्वी पाकिस्तान में अत्यधिक कर लगाने वाली और खतरनाक स्थिति पैदा कर दी, जिसने भारत को मानवीय आधार पर, पूर्व में रहने वाले बंगालियों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान। 95 पाकिस्तान सरकार को लगता है कि पूर्व-पश्चिम पाकिस्तान में आंतरिक राजनीतिक तनाव का उसके शत्रुतापूर्ण पड़ोसी भारत द्वारा पूरी तरह से उपयोग किया गया था, जिसने न केवल भौगोलिक रूप से देश के दो हिस्सों को विभाजित किया, बल्कि पाकिस्तान में आंतरिक तनाव को बढ़ाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। देश अपने सैद्धांतिक दुश्मन (पाकिस्तान) को कमजोर करने और जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत को मानने की दोहरी उम्मीदों में। 96 1970 तक पूर्वी बंगाल के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से मुक्ति के लिए अपना समर्थन नहीं दिया। मुजीब की अवामी लीग के आधार पर पूर्वी बंगाल में सत्ता के हस्तांतरण को रोकने के लिए जनरल याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रयासों ने पूर्वी बंगाल में एक तेज और हिंसक विरोध और प्रतिक्रिया पैदा की और जिसने लोगों को मजबूर किया पूर्वी बंगाल ने अपने वैध अधिकारों को हासिल करने और शोषण के युग को समाप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अवामी लीग को सत्ता हस्तांतरित करने में जनरल याह्या खान की विफलता, जिसने दिसंबर 1970 के चुनावों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, मार्च 1971 में शेख मुजीब की गिरफ्तारी और पूर्वी बंगाल के लोगों पर सैन्य कार्रवाई ने पश्चिम पाकिस्तान के खिलाफ क्रांति को जन्म दिया। और बांग्लादेश को एक संप्रभु गणराज्य घोषित करने के लिए। प्रारंभ में भारत ने पाकिस्तान के आंतरिक मामलों से दूर रहने की अपनी नीति को कड़ाई से बनाए रखने का निर्णय लिया। इसने पूर्वी बंगाल में होने वाली घटनाओं को खतरे की दृष्टि से देखा लेकिन पूर्ण तटस्थता बनाए रखने का निर्णय लिया।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

संकट पर भारत सरकार की प्रारंभिक प्रतिक्रिया बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सहानुभूति की अभिव्यक्ति तक ही सीमित थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 27 मार्च, 1971 को कहा कि, भारत पूर्वी बंगाल के विकास के साथ "यथासंभव निकट संपर्क" में रहेगा और उचित निर्णय लेगा। स्वर्ण सिंह, तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री ने आशा व्यक्त की कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं "वहां के अधिकांश लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगी।" संसद ने सर्वसम्मति से जीवन के लोकतांत्रिक तरीके के लिए अपने संघर्ष में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ भारत की गहरी सहानुभूति और एकजुटता का संकल्प लिया। प्रारंभ में, भारत सरकार ने एक सीमित कार्रवाई की योजना बनाई। भारतीय सीमा सुरक्षा बल को स्वतंत्रता सेनानियों या 'मुक्ति वाहिनी' की मदद के लिए कुछ लोगों और सामग्रियों को भेजने की अनुमति दी गई थी, जबकि भारतीय सेना को सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था।98 मुक्ति बाहिनी को दिए गए समर्थन के बावजूद, भारत अभी भी उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान पूर्वी बंगाल संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहमत होगा, मुजीब को रिहा करेगा, पूर्वी बंगाल के निर्वाचित नेताओं के साथ बातचीत करेगा और एक समझौता करेगा जो उन्हें स्वीकार्य हो और सुरक्षा की भावना पैदा करे ताकि शरणार्थी वापस जा सकें। नई दिल्ली ने भी बार-बार यह स्टैंड लिया कि यह मुद्दा या तो पाकिस्तान की आंतरिक समस्या नहीं है या भारत-पाकिस्तान विवाद का नहीं है, बल्कि यह समस्या एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ता है, समस्या के कारण इसकी सुरक्षा को खतरा है। भारत में शरणार्थियों की भारी आमद। 99 भारत के लिए, शरणार्थियों की भारी आमद से निपटने की

प्रत्यक्ष लागत चौंका देने वाली थी। अप्रत्यक्ष लागत – भारत के विकास और अर्थव्यवस्था पर शरणार्थी प्रवाह का दीर्घकालिक प्रभाव और भी बुरा था।

शरणार्थियों की बाढ़ के कारण प्रभाव

शरणार्थियों की बाढ़ के कारण पूर्वी पाकिस्तान के घटनाक्रम का भारत पर तत्काल प्रभाव पड़ा। शुरुआती भारतीय प्रतिक्रिया, हालांकि तीखी थी, चौकस थी। नई दिल्ली में नेतृत्व इस धारणा से बचना चाहता था कि वह पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली प्रतिरोध को तुरंत समर्थन देने के लिए तैयार था। हालाँकि, यह सावधानी लंबे समय तक नहीं रही क्योंकि अप्रैल 1971 के मध्य में भारत ने कलकत्ता के पास अवामी लीग कार्यालय की स्थापना की अनुमति दी और 17 अप्रैल को बैद्यनाथ ताला से 'निर्वासित सरकार' की घोषणा की अनुमति दी, जिसे लोकप्रिय रूप से 'के रूप में जाना जाता है। मुजीबनगर'। कलकत्ता के पास एक रेडियो फ्री बांग्ला स्थापित किया गया था और 18 अप्रैल को, पार्क सर्कस, कलकत्ता में पाकिस्तानी उप उच्चायोग को पाकिस्तान विदेश सेवा, हुसैन अली से एक पूर्वी बंगाली दलबदलू ने अपने कब्जे में ले लिया था और उस समय से, इसने कार्य किया था। भारत के मौन सहयोग से भारत के लिए बांग्लादेश का वास्तविक मिशन। अवामी लीग के कई प्रमुख अधिकारी, जिनमें ताजुद्दीन अहमद, नजरूल इस्लाम, मंसूर अली और कर्नल एम.ए.जी. उस्मानी ने भी कलकत्ता में शरण ली थी। उन्हें शेक्सपियर सरानी, कलकत्ता में एक सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति में रखा गया था। एक बार जब राजनीतिक नेतृत्व कलकत्ता में सुरक्षित रूप से स्थापित हो गया, तो भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बंगाली गुरिल्ला बल 'मुक्ति वाहिनी' (शाब्दिक अर्थ मुक्ति बल) को हथियार, प्रशिक्षण और अभयारण्य प्रदान करना शुरू कर दिया। 'मुक्ति वाहिनी' छात्रों, सिविल सेवकों और पूर्वी पाकिस्तानी राइफल्स (ईपीआर) के पूर्व सदस्यों से बनी थी। उन्हें पूर्व पाकिस्तानी सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल उस्मानी की कमान में रखा गया था। सैन्य अभियानों के संचालन के दौरान मुक्ति बाहिनी ने पश्चिमी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी पाकिस्तान में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के जवाब में भारत ने जो पहला कदम उठाया, वह पूर्वी पाकिस्तान में लोकतंत्र की जीत के लिए अपनी स्पष्ट सहानुभूति और पाकिस्तान के लोगों की वैध आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए (पूरी तरह से) व्यक्त किया गया था। दिसंबर 1970 और जनवरी 1971 के चुनाव, सैन्य कार्रवाई और शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, अवामी लीग के वरिष्ठ नेता भारत भाग गए और निर्वासित सरकार की स्थापना के लिए भारतीय समर्थन मांगा। भारत ने जो पहला औपचारिक कदम उठाया, वह सैयद नजरुल इस्लाम और ताजुद्दीन अहमद के नेतृत्व में ऐसी सरकार की स्थापना थी। दूसरा कदम पूर्वी बंगाली सैन्य और अर्ध-सैन्य कर्मियों को शरण देना था जो भारत भाग गए थे क्योंकि वे 25 मार्च, 1971 से जनरल टिक्का खान द्वारा आयोजित व्यापक सैन्य कार्रवाई के विशेष लक्ष्य थे।102 स्वतंत्र और संप्रभु बांग्लादेश गणराज्य 26 मार्च, 1971 को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा घोषित किया गया था। बांग्लादेश के नए घोषित गणराज्य की सरकार की ओर से एक विशेष मिशन नई दिल्ली और अन्य विश्व की राजधानियों और संयुक्त राष्ट्र में भेजा गया था। बांग्लादेश की सरकार ने भारत, सीलोन (अब श्रीलंका) और दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों से सरकार के गठन पर ध्यान देने और इसे मान्यता देने और इसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की अपील की। भारत सरकार के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न था कि बांग्लादेश गणराज्य को मान्यता दी जाए या नहीं, विशेष रूप से तब जब उसके नियंत्रण में कुछ क्षेत्र के साथ एक अनंतिम सरकार स्थापित की गई और मान्यता मांगी गई।

भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थी समस्या के रूप में पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे को उठाया। न्यूयॉर्क और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालयों में हमारे राजदूतों को पूर्वी पाकिस्तान में हिंसक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में ECOSOC (आर्थिक और सामाजिक परिषद), UNHCR (शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग), और अन्य संबंधित एजेंसियों को विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। और पूर्वी पाकिस्तान के पड़ोसी भारतीय राज्यों पर आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक दबावों के संदर्भ में भारत पर इसका

नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसी तरह के निर्देश सभी राजनयिक मिशनों को उन सभी सरकारों से समर्थन जुटाने के लिए दिए गए जिनके लिए वे मान्यता प्राप्त थे।

कोर ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान संकट को हल करने के लिए नीतिगत दृष्टिकोण पर निर्णय लिया और अंतरिम सिफारिशों की विफलता के मामले में भारत सैन्य विकल्पों का प्रयोग करेगा। भारत ने निम्नलिखित तत्वों वाले नीतिगत दृष्टिकोण पर निर्णय लिया:

पाकिस्तानी सरकार ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और जानबूझकर पूर्वी पाकिस्तान में अलगाववादी आंदोलन खड़ा करके और उसे खुला सैन्य समर्थन देकर पाकिस्तान को विभाजित करने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान ने मुजीबुर रहमान को बिना शर्त रिहा करने या उसके साथ राजनीतिक वार्ता फिर से शुरू करने के भारतीय सुझाव का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान यह प्रचार करने में भी लगा रहा कि भारत में आने वाले शरणार्थी विद्रोही और "अलगाववादी बदमाश" थे और उनमें से अधिकांश हिंदू थे। इसने भारत पर निर्वासन में सरकार और पूर्वी पाकिस्तानी प्रतिरोध समूहों को समर्थन देने का भी आरोप लगाया - एक आरोप जिसमें कुछ हद तक सच्चाई थी। पाकिस्तान के अपने टकरावादी रुख से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं थे। भारत सरकार तेजी से महसूस करने लगी कि पूर्वी पाकिस्तानियों (बांग्लादेशियों) के मुक्ति संग्राम के समर्थन में सैन्य विकल्प का प्रयोग अपरिहार्य है। 110 इस संभावना की तैयारी में भारत ने जो सबसे गंभीर रणनीतिक कदम उठाया, वह 7 अगस्त, 1971 को शांति, मित्रता और सहयोग पर भारत-सोवियत समझौते पर हस्ताक्षर करना था। जहां तक भारत का संबंध था, समझौते का सामान्य उद्देश्य था किसी देश द्वारा भारत की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में सोवियत सहायता प्राप्त करने के लिए कानूनी और राजनीतिक आधार प्रदान करना। दूसरा और सबसे विशिष्ट उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान, या पाकिस्तान और चीन के किसी भी सैन्य अभियान को विफल करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की स्थिति में सोवियत संघ से भविष्य के समर्थन के लिए एक आधार प्रदान करना था, जिसे भारत बांग्लादेश की मुक्ति के समर्थन में कर सकता है।

बांग्लादेश में विकास प्रेरित अनैच्छिक पुनर्वास

भारी आर्थिक विकास से जुड़ी बढ़ती ऊर्जा और परिवहन मांगों को पूरा करने के लिए, बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए विकास परियोजनाओं जैसे राजमार्गों और बांधों को विकासशील देशों में व्यापक रूप से लागू किया गया है। ऐसी कई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण के लिए तय किए गए क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के अनैच्छिक पुनर्वास की आवश्यकता होती है। पिछले 20 वर्षों में, दुनिया भर में 250-300 मिलियन लोग विकास और संबंधित मुद्दों के कारण विस्थापित हुए हैं, और इनमें से कई व्यक्तियों को हाशिए पर रखा गया है और पर्याप्त मुआवजे या बहाली उपायों तक पहुंच के बिना छोड़ दिया गया है (एडीबी, 2006, मोदी, 2009)। इस तरह के विकास-प्रेरित अनैच्छिक पुनर्वास ने कई देशों में तेजी से गंभीर सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक समस्याएं पैदा की हैं, और इस प्रकार विकास एजेंसियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय दाताओं ने इन मुद्दों से बेहद चिंतित हो गए हैं, अनैच्छिक पुनर्वास न केवल भूमि हानि को प्रेरित करता है बल्कि प्रभावित निवासियों के लिए विभिन्न जोखिम। गरीबी जोखिम और पुनर्निर्माण (आईआरआर) मॉडल को अनैच्छिक पुनर्वास में निहित चुनौतियों की चर्चा में व्यापक रूप से अपनाया गया है, क्योंकि यह मॉडल उन जोखिमों को उजागर करता है जिनका सामना विस्थापित व्यक्ति अनैच्छिक पुनर्वास के साथ करते हैं, और इन जोखिमों को कम करने के तरीके भी सुझाते हैं। इस मॉडल में, सर्निया ने नौ संभावित जोखिमों की पहचान की जो अन्योन्याश्रित रूप से विस्थापन में शामिल हैं: भूमिहीनता, बेरोजगारी, बेघर होना, हाशियाकरण, खाद्य असुरक्षा, बढ़ती रुग्णता, सामान्य संपत्ति संसाधनों तक पहुंच का नुकसान, शिक्षा की हानि, और सामाजिक असंबद्धता। इन जोखिमों में से, पुनर्निर्माण भूमिहीनता और बेरोजगारी के उपायों का विस्थापित लोगों के जीवन को बहाल करने में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है क्योंकि आवास और रोजगार खोजने के साथ-साथ संपत्ति हासिल करना पुनर्निर्माण और अन्य गरीबी जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है (डिकिन्सन और

वेबर, 2007, क्वेटुलियो-नवारा एट अल) ., 2014)। साथ ही, दरिद्रता के जोखिम मनोवैज्ञानिक कल्याण सहित विस्थापन के कल्याणकारी पहलुओं से संबंधित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से आजीविका बहाली के साथ तालमेल बिठा सकती है, लेकिन अनैच्छिक पुनर्वास में अक्सर इसकी उपेक्षा की जाती है। बेघर होने का जोखिम मूल स्थान से लगाव की भावना (हानि) से निकटता से जुड़ा हुआ है, और कई मामलों में मुआवजे या पुनर्वास प्रक्रियाओं में बहाली के हिस्से के रूप में इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसके अलावा, संभावित व्यापक को ध्यान में रखते हुए –गरीबी के जोखिमों के विभिन्न प्रभावों, अनैच्छिक पुनर्वास के परिणामों का मूल्यांकन कानूनी रूप से आवश्यक मुआवजे की प्राप्ति के बजाय पुनर्वास के बाद प्रभावित लोगों और उनके जीवन की गुणवत्ता के बीच संतुष्टि के आधार पर किया जाना चाहिए।

कई विकास-प्रेरित अनैच्छिक पुनर्वास परियोजनाओं में भूमिहीनता, बेरोजगारी, और अन्य गरीबी के जोखिम आमतौर पर देखे जाते हैं, लेकिन जोखिम प्रभावों की संवेदनशीलता घरों और विकास परियोजनाओं दोनों में भिन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रभाव अक्सर प्रभावित लोगों द्वारा अनपेक्षित होते हैं, और यह विशेष रूप से तब लागू होता है जब लोग नए क्षेत्रों में प्रवास करते हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियाँ उन क्षेत्रों से भिन्न हो सकती हैं जिनमें ये लोग पहले रहते थे। अनैच्छिक पुनर्वास ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास की सुविधा प्रदान कर सकता है, जैसा कि सामान्य तौर पर, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक व्यावसायिक और शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए अक्सर रहने की लागत में वृद्धि की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से आवास में, और सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा को प्रेरित करता है। इस संबंध में, विस्थापन के परिणामस्वरूप ग्रामीण-शहरी प्रवास गरीबी के जोखिमों के बारे में बढ़ती संवेदनशीलता से संबंधित हो सकता है। विस्थापित लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर ग्रामीण-शहरी प्रवासन के प्रभावों के साथ-साथ इन प्रवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शमन उपायों को प्रभावित और साइट-विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की विशेषताओं के आधार पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है।

कई अन्य देशों की तरह, पिछले कुछ दशकों के दौरान बांग्लादेश में तेजी से शहरीकरण हुआ है; इसने पिछले दशक में 1.4% की वार्षिक दर से निरंतर जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है, जिसने राष्ट्रीय जनसंख्या को 124 मिलियन (2001) से बढ़ाकर 142 मिलियन (2011) (बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो, 2011) कर दिया है। 1960 के दशक के बाद से, ग्रामीण-शहरी प्रवासन के परिणामस्वरूप जनसंख्या ने ढाका और चटगांव जैसे शहरी केंद्रों में उल्लेखनीय और निरंतर वृद्धि दिखाई है, एक अनुभवजन्य सर्वेक्षण में पाया गया कि बांग्लादेश में शहरी क्षेत्रों में प्रवासन के लिए प्रमुख ड्राइविंग बल आर्थिक हैं, जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों सहित नौकरियों की उपलब्धता, और व्यावसायिक रूप से केंद्रीय स्थानों में बेहतर अवसर शहरी क्षेत्रों में विषम जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के साथ-साथ आय में वृद्धि के बीच अंतर शहरी केंद्रों के भीतर अमीर और गरीब, लंबे समय से बांग्लादेश में महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे रहे हैं।

कई अन्य विकासशील देशों की तरह, बांग्लादेश में भी विकास-प्रेरित अनैच्छिक पुनर्वास आम है। 1971 में स्वतंत्रता के बाद से, देश में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं ने सालाना 50,000 व्यक्तियों को प्रभावित किया है, और इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप 1994 और 2004 के बीच कुल 7000 हेक्टेयर का अधिग्रहण हुआ है, हालांकि, बांग्लादेश में भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास तेजी से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं। , जैसा कि हाल के नागरिक विरोधों की प्रमुखता से देखा जा सकता है, इसके अलावा, ये कारक देश में उच्च जनसंख्या घनत्व और भूमि की कमी के कारण बढ़ गए हैं।

बांग्लादेश में प्रमुख विकास-प्रेरित अनैच्छिक पुनर्वास कार्यों में जमुना बहुउद्देश्यीय पुल परियोजना (JMBP) शामिल है जिसके लिए 2900 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है और

इससे 105,000 व्यक्ति प्रभावित होते हैं, और भैरब पुल परियोजना (BBP) जिसके लिए 17 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है और 4000 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। जेएमबीपी के दौरान पुनर्वास, जो बांग्लादेश में हाल के बुनियादी ढांचे के विकास में सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण का मामला था, मुख्य रूप से ग्रामीण सेटिंग्स के भीतर पूरा किया गया था और इसमें नागरिक सुविधाओं के साथ-साथ आजीविका बहाली कार्यक्रमों के साथ सामुदायिक पुनर्वास शामिल था। बीबीपी में पुनर्वास तुलनात्मक रूप से छोटे पैमाने पर था देश में अन्य हालिया विकास परियोजनाओं के लिए; हालाँकि, यह प्रक्रिया अद्वितीय थी क्योंकि इसे अर्ध-शहरी सेटिंग्स में लागू किया गया था। बीबीपी के लिए पुनर्वास पैकेज में विकास परियोजना में रोजगार सहित वाणिज्यिक भूखंडों का पुनर्निर्माण और आजीविका बहाली शामिल है। इन मामलों को इस मायने में सफल माना जा सकता है कि उन्होंने पुनर्वास के बाद प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास गतिविधियाँ प्रदान कीं। हालाँकि, बांग्लादेश में कई अन्य विकास-प्रेरित अनैच्छिक पुनर्वास कार्यों ने कानूनी रूप से आवश्यक नकद मुआवजे और बाहरी फंडिंग एजेंसियों के दिशानिर्देशों पर ध्यान केंद्रित किया, और उनमें सामुदायिक पुनर्निर्माण और आजीविका बहाली जैसे पुनर्वास और पुनर्वास कार्यक्रमों पर जोर नहीं दिया गया।

रोड नेटवर्क इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट II (RNIMP-II), जिसके लिए ऋण प्रावधान एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्त पोषित 2014 में पूरा किया गया था, बांग्लादेश में हाल की कई प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में से एक था; इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और जिला सड़क संयोजनों के निर्माण और रखरखाव के माध्यम से परिवहन दक्षता में सुधार करना और एकीकृत सड़क नेटवर्क को मजबूत करना था। इसने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में निवासियों को प्रभावित किया (एडीबी, 2014, संचार सड़क और राजमार्ग विभाग, 2008 मंत्रालय)। चार अनुबंध पैकेजों में से चटगाँव अनुबंध इसकी आबादी के संदर्भ में उल्लेखनीय है। यहाँ, चटगाँव जिला (जिला), जो चटगाँव अनुबंध में शामिल था, परियोजना क्षेत्रों में सबसे अधिक आबादी वाला है; इसकी आबादी 7.5 मिलियन है और यह राजधानी ढाका (11.88 मिलियन) के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला केंद्र है। ढाका जिला (1.8%) (बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, 2011, संचार सड़क और राजमार्ग विभाग मंत्रालय, 2008. इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत उच्च जनसंख्या घनत्व, राष्ट्रीय औसत 964 की तुलना में 1421 व्यक्ति प्रति किमी2, दक्षिणी बांग्लादेश में एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र के रूप में इसकी स्थिति के साथ-साथ जिले के भीतर और भीतर बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या गतिशीलता को इंगित करता है। ये कारक प्रभावित कर सकते हैं प्रभावित परिवारों का स्थानांतरण व्यवहार और अनैच्छिक पुनर्वास में निहित गरीबी जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता। अर्थात्, मूल स्थानों से विस्थापन के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में प्रवास की सुविधा हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मजबूर अवसरों के रूप में देखा जा सकता है। रहने के लिए बेहतर स्थानों की तलाश करने के लिए। साथ ही, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच मौजूदा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण, अनैच्छिक पुनर्वास द्वारा स्थानांतरित ग्रामीण क्षेत्रों के इन अर्ध-शहरी और शहरी प्रवासियों को उन लोगों की तुलना में गरीबी के तीव्र जोखिम का सामना करना पड़ सकता है जो अपने मूल स्थान।

निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन के दो उद्देश्य विस्थापन के बाद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के इरादे की पहचान करना था, जिसमें शहरी और ग्रामीण असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था, और बांग्लादेश में विकास-प्रेरित अनैच्छिक पुनर्वास के परिणामस्वरूप ग्रामीण-शहरी प्रवास पर संभावित तीव्र गरीबी जोखिमों को स्पष्ट करना था। वर्तमान अध्ययन ने दो परिकल्पनाओं की जांच की: (1) बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने का इरादा रखते हैं, उनकी तुलना में जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहना चाहते हैं, और (2) सामाजिक-आर्थिक असमानताएं और पुनर्वास से संबंधित हैं इच्छित ग्रामीण-शहरी स्थानांतरण

और अन्य अपेक्षित स्थानांतरण पैटर्न के बीच स्थिति कारक। ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के भीतर स्थानांतरण, जिससे गरीबी के जोखिम में वृद्धि होगी।

- पूर्वी पाकिस्तान संकट का समाधान केवल तभी हो सकता है जब पाकिस्तान आम चुनावों के परिणामों का सम्मान करे और पाकिस्तान के लोगों की वैध राजनीतिक और संवैधानिक आकांक्षाओं की पूर्ति का आश्वासन दे।
- इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सैन्य शासन को तुरंत शेख मुजीबुर रहमान को हिरासत से रिहा कर देना चाहिए, जिससे वह ढाका लौट सकें और उनके साथ राजनीतिक बातचीत की सिफारिश कर सकें।
- पाकिस्तान को सभी पूर्वी पाकिस्तान शरणार्थियों की उनके घरों में वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक कल्याण की गारंटी देने का वचन देना चाहिए।
- पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर सैन्य कार्रवाई तत्काल रोक देनी चाहिए। पाकिस्तानी सैनिकों को बैरकों में लौट जाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांतिपूर्ण तरीकों से पूर्वी पाकिस्तान संकट को हल करने के लिए पाकिस्तान को प्रभावित और दबाव डालना चाहिए। यह सलाह और दबाव द्विपक्षीय राजनयिक चैनलों और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से उत्पन्न किया जाना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों को भारत में रह रहे लाखों पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों और सैन्य कार्रवाई के कारण पूर्वी पाकिस्तान में आश्रयहीन हो चुके लोगों को राहत और पुनर्वास सहायता देने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए और पाकिस्तानी पर दबाव बनाने के लिए इसका पालन करना चाहिए पूर्वी पाकिस्तान में लोकतंत्र को पुनर्जीवित करेगी

संदर्भ

1. मोहम्मद अमीनुल करीम, बांग्लादेश-भारत संबंध: कुछ हालिया रुझान "- जर्नल ऑफ़ बांग्लादेश स्टडीज़, वॉल्यूम: 11. नंबर 2. 2009।
2. कंवल सिब्बल, "इंडियाज़ रिलेशंस विथ इट्स नेबर्स", इंडिया क्वार्टरली, वॉल्यूम LXV, नंबर 1, जनवरी-मार्च, 2009। 34
3. पियाली दत्ता "भारत-बांग्लादेश संबंध मुद्दे, समस्याएं और हालिया विकास" शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान (आईपीसीएस), नई दिल्ली, 2010।
4. त्रिदिब चक्रवर्ती, "2010 में दक्षिण एशिया के साथ भारत के संबंध: क्रेस्ट्स एंड ट्रॉज की यात्रा", वर्ल्ड फोकस, नवंबर-दिसंबर, 2010।
5. संतोष सिंह, "भारत-बांग्लादेश संबंध", वर्ल्ड फोकस, फरवरी 2010।
6. वाई.एम. बम्मी, "इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस द वे फॉरवर्ड" विज बुक स्टोर पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2010।
7. अरविंद कुमार, "भारत-बांग्लादेश संबंध" तीसरी अवधारणा, सितंबर 2011।
8. डी.आर. मनकेकर "ट्वेंटी-टू फेटफुल डेज: पाकिस्तान कट टू साइज", नटराज पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2011।
9. प्रमोद कुमार, "भारत की आर्थिक नीति अपने पड़ोसियों की ओर", वर्ल्ड फोकस, जून 2011।